>

Title : Issue regarding allotment of land to the people in Andaman & Nicobar Islands.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): Mr. Chairman, Sir, many, many thanks to you. Please allow me to speak from here. अण्डमान लक्ष्यद्वीप समूह में असेंबली नहीं होने कारण द्वीपों का विकास और द्वीपवासियों की तकलीफों को देखते हुए, सन् 1980 में एक अथॉरिटी बनायी गई थी, जिसका नाम दिया गया था आइलैण्ड डिवेल्पमेंट अथॉरिटी। उस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। उसी मुताबिक उसका आदेश था कि साल में कम से कम चार बार मीटिंग हो और द्वीप समूहों की समस्या का समाधान हो। 19 जनवरी 2003 को एनडीए सरकार के कार्यकाल में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोर्ट ब्लेयर शहर में आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग की थी, डिसीजन लिया था और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट लिखित में दी डेली टेलीग्राम्स पत्रिका में 20 जनवरी 2003 को छपा था। जो डिसीजन हुआ था, लिस्ट नं0 1, जो अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के प्री-42, सैटलर्स और जो आजादी के पहले आये थे, उनके वंशजों को, हर परिवार को सरकार एक हैक्टेअर जमीन देगी। उसी समय पर फैसला हुआ था कि राष्ट्रीय राजमार्ग डिग्लीपुर से पोर्ट ब्लेयर 333 किलोमीटर तक बनेगा। उसके मुताबिक आज से तीन साल पहले जमीन का सर्वे भी हुआ, करीब-करीब 16, 270 हैक्टेअर डीम्ड फॉरेस्ट का सर्वे हुआ। सुनामी के पश्चात लैंड ऊंचा हो गया, वह सर्वे हो चुका है और करीब चार हजार हैक्टेअर जमीन मिली। कुल मिलाकर 2 लाख 10 हजार बीघा जमीन हमारे यहां उपलब्ध है, लेकिन वर्ष 2003 का डिसीजन, जो आईडीए मीटिंग में हुआ था, प्री-42, सैटलर्स और आजादी के पहले जो लोग आये थे, उनके वंशजों को एक हैक्टेअर लैंड अलॉटमेंट करने के लिए कहा था। आज लैंड हाथ में है, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। इस बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से सम्पर्क किया, पत्र लिखा, आईडीए की मीटिंग के लिए एजेंडा दिया था। केवल एक बार प्रधानमंत्री जी ने 15 जून 2011 को 40 मिनिट्स के लिए मीटिंग की थी, लेकिन हमारे एजेंडे तथा 10वीं आईडीए मीटिंग में जो डिसीजन 19 जनवरी 2003 को हुआ था, उस पर चर्चा नहीं हुई। मैं आपसे मांग करूंगा कि 10 साल बीतने के पश्चात भी उन डिसीजंस पर अमल नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि सैटलर्स, प्री-42 और आजादी के पहले जो लोग आये थे, उनके वंशजों को सरकार के द्वारा एक हैक्टेअर लैंड दी जाये, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाये। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस मांग को पूरा करें।